नीति

राज्य स्तरीय इम्पावर्ड कमेटी की बैठक में 52 प्रस्तावों को मिली हरी झंडी

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 300 करोड़ रुपये का होगा निवेश : दीपक कुमार

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के तहत गठित राज्य स्तरीय इम्पावर्ड कमेटी की बैठक में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने की रणनीति बनाई गई। समिति की बैठक में बुधवार को 54 प्रस्ताव परीक्षण व निर्णय के लिए प्रस्तुत किए गए, जिनमें 52 को मंजूरी दी गई। कृषि उत्पादन आयुक्त दीपक कुमार की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई बैठक में बताया गया कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा व उत्तराखंड के उद्यमियों द्वारा रामपुर में लगभग 300 करोड़ का निवेश किया जा रहा है।

खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ाव देने के लिए मटर, गाजर, गोभी, पालक, मशरूम आदि के प्रसंस्करण की इकाई स्थापित की जा रही हैं। अब तक 700 करोड़ के प्रस्ताव पारित

700 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी, 150 करोड़ रुपये दिया जाएगा अनुदान

हैं, जिसमें लगभग 150 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा। गोरखपुर-वाराणसी के उद्यमियों द्वारा लगाए गए प्लांट पर सोलर संयंत्र लगाया जा रहा है, जिसमें 75 किलोवाट पर 50 लाख तक का अनुदान दिया जाएगा। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अपर मुख्य सचिव बीएल मीना ने बताया कि अब तक हुई 10 बैठकों में 331 प्रस्तावों की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

समिति को यह भी अवगत कराया गया कि रेडी टू ईट के 62, सोलर पावर के 58, आईक्यूएफ के 31, सिरियल्स, पल्स के 26, कैटल फीड के 22, फल व सब्जी प्रसंस्करण के 21, दुग्ध प्रसंस्करण के 14, रेडी टू सर्व के 12, बेकरी के 11, मसाला प्रसंस्करण के 11, फोर्टिफाइड राइस के 10, मस्टर्ड आयल के 10, राइस ब्रान ऑयल के 9, मल्टीग्रेन आटा के 8, गुड़ प्रसंस्करण के 8, मेडिसिनल ऑयल के 3, चिकोरी प्रसंस्करण, आइस क्रीम कोन, मीट प्रसंस्करण तथा हींग व शहद प्रसंस्करण के 1-1 प्रोजेक्ट स्वीकृत किए गए हैं।

रामपुर व बरेली फ्रोजन फूड प्रोसेसिंग हब के रूप में नीति अंतर्गत उभर कर आया है। प्रदेश के निवेशकों के साथ-साथ उत्तराखंड व राजस्थान के उद्यमी द्वारा इन जिलों ने लीज पर भूमि लेकर फ्रोजेन फूड प्रासेसिंग की यूनिट की स्थापना की जा रही है। अनुबंध करने के साथ केंद्र सरकार की सीडीपी योजना अंतर्गत निवेशकों द्वारा प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। इसे केंद्र सरकार को स्वीकृति के लिए भेजा गया है।